राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर

एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 16564/2021

बंशीलाल पुत्र स्व. हेमा जी, उम्र लगभग 75 वर्ष, जाति नाई, निवासी-गाँव - रूपावास, तहसील - पाली, जिला - पाली, (राज.)----याचिकाकर्ता।

बनाम

1. जिला कलेक्टर, पाली के माध्यम से, राजस्थान राज्य (राज.)

2. चम्पालाल पुत्र स्व. हेमा जी, उम्र लगभग 65 वर्ष, बी/सी - नाई, निवासी गाँव - रूपावास, तहसील - पाली, जिला - पाली, (राज.)

3. सरपंच, ग्राम पंचायत रूपावास, तहसील-पाली, जिला - पाली, (राज.)----प्रतिवादी।

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए:- श्री निरुपम गुप्ता।

माननीय जस्टिस श्री विनीत कुमार माथुर

आदेश

रिपोर्ट योग्य

08/02/2024

1. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को सुना।

2. वर्तमान रिट याचिका जिला कलेक्टर, पाली द्वारा पारित दिनांक 15.01.2018 के आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें याचिकाकर्ता को जारी पट्टा रद्द कर दिया गया था।

3. संक्षेप में इस मामले में तथ्यों का उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता ने ग्राम पंचायत, रूपवास के समक्ष पैतृक आवासीय भूखंड का पट्टा देने के लिए 10.06.2014 को एक आवेदन दायर

किया था, जिस पर उसका कब्जा था। कार्यवाही के दौरान, प्रतिवादी संख्या 2 चम्पालाल द्वारा एक आपत्ति दायर की गई थी, जो याचिकाकर्ता का भाई है। हालाँकि, ग्राम पंचायत, रूपावास ने याचिकाकर्ता के पक्ष में पट्टा संख्या 78 दिनांक 27.10.2014 प्रदान किया। याचिकाकर्ता को पट्टा देने के खिलाफ, प्रतिवादी संख्या 2 ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत जिला कलेक्टर, पाली के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की। जिला कलेक्टर, पाली ने पक्षकारों को सुनने के बाद प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार कर लिया और याचिकाकर्ता के पक्ष में जारी पट्टा को रद्द कर दिया। इसलिए, वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के पास 40-50 वर्षों से अधिक समय से विचाराधीन भूखंड/संपत्ति का कब्जा है। वह आगे प्रस्तुत करता है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत एक आवेदन पर, ग्राम पंचायत ने उचित प्रक्रिया को अपनाने के बाद, याचिकाकर्ता के पक्ष में पट्टा प्रदान किया। वह प्रस्तुत करता है कि पुनरीक्षण प्राधिकरण ने दिनांकित 15.01.2018 आदेश पारित करते समय एक त्रुटि की, जिसके तहत याचिकाकर्ता को जारी किया गया पट्टा रद्द कर दिया गया है। विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि प्रतिवादी संख्या 2 ने भी विभाजन और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमा दायर किया है और यह पाली में दीवानी अदालत के समक्ष विचाराधीन है। इसलिए, वह प्रार्थना करता है कि रिट याचिका की अनुमति दी जाए और जिला कलेक्टर, पाली द्वारा पारित 15.01.2018 दिनांकित आदेश को रद्द किया जाए और अलग किया जाए।

5. मैंने बार में की गई दलीलों पर विचार किया है और 15.01.2018 दिनांकित आदेश सहित मामले के प्रासंगिक रिकॉर्ड को देखा है।

6. वर्तमान मामले में स्वीकार किए गए तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता एक पैतृक भूखंड/संपत्ति पर कब्जा कर रहा है जिसके लिए उसने पट्टा देने के लिए ग्राम पंचायत में आवेदन किया था। प्रत्यर्थी संख्या 2 ने याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए उक्त आवेदन पर आपत्ति दर्ज की, प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा दायर आपत्ति के बावजूद पट्टा ग्राम पंचायत, रूपवास द्वारा जारी किया गया था।

7. दलीलों से, यह स्पष्ट है कि हेमाजी (याचिकाकर्ता के पिता) के चार बेटे और एक बेटी थी और विचाराधीन संपत्ति एक पैतृक संपत्ति थी, इसलिए, प्रतिवादी संख्या 2 (याचिकाकर्ता के भाई) द्वारा आपत्ति उठाए जाने के बावजूद, पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा याचिकाकर्ता के नाम पर एकल रूप से जारी किया गया था। विभाजन का मुकदमा भी दीवानी अदालत के समक्ष विचाराधीन है जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विचाराधीन संपत्ति एक पैतृक संपत्ति है और याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा अभी भी सीमांकित और विभाजित किया जाना था। यह भी ध्यान दिया जाता है कि आवेदन में ही याचिकाकर्ता ने संपत्ति को पैतृक संपत्ति बताया था। चूँकि संपत्ति एक पैतृक संपत्ति है और इसे याचिकाकर्ता के भाइयों और बहनों के बीच विभाजित/विभाजित नहीं किया गया है, इसलिए पट्टा अकेले याचिकाकर्ता को जारी नहीं किया जा सकता था, विशेष रूप से जब उसके भाई यानी प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा आपत्ति उठाई गई थी। पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष पूरी तरह से उचित है और जब तक याचिकाकर्ता यह दिखाने में सक्षम नहीं होता है कि संपत्ति अकेले उसकी है और भाइयों और बहनों के बीच कोई विवाद नहीं है, तभी याचिकाकर्ता के पक्ष में पट्टा जारी किया जा सकता था।

चूंकि पैतृक संपत्ति में भाइयों और बहनों के हिस्से के बीच विवाद है, इसलिए ग्राम पंचायत ने केवल याचिकाकर्ता के नाम पर पट्टा जारी करने में गलती की।

8. इस न्यायालय का दृढ़ मत है कि यदि कोई पैतृक संपत्ति है जिसके लिए पट्टा जारी किया जाना है और संपत्ति में शेयरों को वितरित और विभाजित नहीं किया गया है, तो पट्टा का आवंटन एक पक्ष के पक्ष में तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि यह प्राधिकरण के समक्ष नहीं लाया जाता है कि अन्य सभी पक्षों ने एक व्यक्ति के पक्ष में अपने अधिकार छोड़ दिए हैं या किसी एक पक्ष के पक्ष में पट्टा देने के संबंध में कोई विवाद नहीं है।

9. ऊपर की गई चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय को प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को अनुमति देने वाले पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश 15.01.2018 में कोई कमजोरी नहीं मिलती है।

10. रिट याचिका किसी भी योग्यता से रहित है और इसलिए इसे खारिज कर दिया जाता है।

(विनीत कुमार माथुर), जे.

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक सुनील कुमार किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा मे समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अँग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।